

राज्या सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2051
16 दिसम्बर 2015 को उत्तर के लिए

इस्पात के आयात में कटौती

2051. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तरी और पूर्वी देशों से इस्पात के आयात में कमी लाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत दो वर्षों में अर्ध-निर्मित इस्पात सहित इस्पात के आयात का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या आयात वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा घरेलू इस्पात उद्योग के संरक्षण और इस्पात के अवांछित क्षेपण पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री

(श्री विष्णु देव साय)

(क): जी नहीं। विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी देशों से इस्पात के आयात को सीमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): गत दो वर्षों और चालू वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान सेमी फिनिशड इस्पात समेत इस्पात आयातों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

मात्रा मिलियन टन में

वर्ष	सेमी फिनिशड इस्पात	कुल फिनिशड इस्पात	कुल इस्पात
2013-14	0.26	5.45	05.71
2014-15	0.70	9.32	10.02
अप्रैल-अक्टूबर 2015-16	0.52	6.68	07.20

स्रोत: जेपीसी

(ग) और (घ): वर्ष 2014-15 और चालू वित्तीय वर्ष में इस्पात के आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण विश्व स्तर पर इस्पात की अधिकतर उपलब्धता होना तथा चीन जैसे महत्वापूर्ण इस्पात उत्पादक देशों में इस्पात की मांग में कमी होना रहा है, जिससे कि इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट हुई है और भारत में आयात करना आकर्षक बन गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए देश में केवल गुणवत्ता पूर्ण इस्पात के आयात की अनुमति हो और घरेलू इस्पात उद्योग सुरक्षित बने सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:-

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गुणवत्ता युक्तन इस्पात का आयात, सरकार ने इस्पालत और इस्पात उत्पाद (गुणवत्तान नियंत्रण) आदेश दिनांक 12.03.2012 को अधिसूचित किया है जिसे अन्तिम बार दिनांक 4.12.2014 को संशोधित किया गया है।
- (ii) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन फ्लैट दोनों इस्पात पर सीमा शुल्क की उच्चांतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।
- (iii) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टील (फ्लैट एवं लांग) स्टेनलैस स्टील (लॉंग और नान-अलॉय लांग उत्पाद पर आयात शुल्क प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया तथा नान अलॉय और अन्य अलॉय फ्लैट उत्पादों पर यह शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है। इसे पुनः अगस्त 2015 में संशोधित करके फ्लैट स्टील पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत, लांग स्टील पर 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और अर्द्ध फिनिशड स्टील पर 7.5 से 10 प्रतिशत किया गया है।
- (iv) सरकार ने नवम्बर, 2014 में निर्देश दिया गया है कि रिबर्स के आयात केवल 'इस्पात उत्पाद गुणवत्तान नियंत्रण आदेश 2012' के अनुसार ही हों, ताकि बोरोन युक्त रिबर्स के सस्ते आयातों को रोका जा सके।
- (v) सरकार ने जून, 2015 में स्टेनलैस स्टील के कतिपय किस्मों के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों के चीन (\$ 309 प्रति टन), कोरिया (\$ 180 प्रति टन) और मलेशिया (\$ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई है।
- (vi) सरकार ने सितम्बर, 2015 में 200 दिनों की अवधि के लिए 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वॉयलों में नान अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों पर 20 प्रतिशत का अनन्तिम सुरक्षोपाय शुल्क लगाया गया है।
